Times of India 28/8/20

mandatory for construction projects that require environmental clearance and ha-

neers, said they had sold more than 200 anti-smog guns. "We sell customised machi-

Landpooling: DDA work on model sectors to begin soon

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Delhi Development Authority's landpooling project may soon see work for the model sectors begin in three zones, as the agency said that it has received a good response.

So far, DDA claims to have pooled 6,575 hectares of land and sectors in zones N, P-II and L may soon be qualify for the policy. These model sectors will set the template for other locations where DDA will play the role of facilitator instead of developer.

A senior DDA official said that a total of 6,219 applications have been registered and 1,371 applications have already been verified by the revenue department of Delhi government.

The landpooling policy is applicable for the urban extension areas of Delhi, comprising 95 villages falling in zones J, K-I, L, N and P-II. The entire area has been divided in to 109 sectors. On an average, each sector is about 250 to 350 hectares, and is anticipated to accommodate about 80,000 to 1 lakh people.

A DDA official explained that for a sector to qualify for development, a minimum of 70% contiguous land in a sector is required to be pooled. Of the pooled land, the developer will retain 60% for development of residential, commercial, public and semi-public facilities while the remaining 40% will be utilised by DDA for development of city infrastructure.

The official said that the rest of the applications are being scrutinised. "DDA is mapping the pooled land on a GIS platform to ascertain the eligibility of sectors, which will be verified by Delhi government," he said. The landpooling policy allows residential FAR of 200 and 15% additional FAR for development of EWS housing.

DDA has developed a web portal for expression of willingness regarding participation in landpooling which was launched last year.

1,412 new ca

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Delhi recorded 1,412 new cases of Covid-19 on Saturday, the city's biggest single-day spike in infections this month, bringing the infection tally to over 1.6 lakh while the death toll rose to 4,284. Fourteen more fatalities linked to infection by the novel coronavirus were recorded in the last 24 hours.

According to the Delhi government's health bulletin, a total of 19,435 tests — 6,090 RTPCR, CBNAAT or TrueNat tests, and 13,345 rapid antigen tests — have been conducted in the last 24 hours.

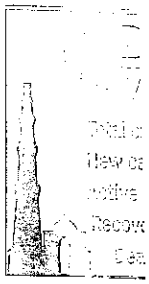

So far 14,12 tests have been the capital whil of tests per mi tion stands at 74,

The positivit at 7.3% while rate is 90%.

In Covid tim local and hot

▷Continued from P1

The tour packages hotels are offering are door-to-door to avoid exposure and create a travel bubble — a car picks you up, takes you to the hotel, and drops you back home.

The industry assessment is that travel will be primarily be local and hotel-centric – budget, premium or luxury, as long as reaching it is easy, sanitisation protocols are convincing, and the location itself is attractive. As a result, even in the restricted universe that travel is right now, there are options galore. Domestic destinations are also hoping to gain over the next few months from the pause in international travel, though restrictions in flights within the country have been a dampener.

Ritu Mehrotra, country manager (India, Sri Lanka & Maldives) for Booking.com, told **TOI**, "People are opting for road trips and holidays within drivable distance in the safety of cars. It will be a while before we reach the pre-Covid-19 levels but we are seeing an appetite for domestic and localised travel in places where restrictions are easing."

Most leading hotel chains, faced with an unprecedented downturn in business, have responded with enthusiasm to sate this appetite for travel.

The interest in its 7-day

ITC has introduce break' at all its lea that lets travellers pickup in a car fr tel's fleet which, maintained by tea in comprehensive tion protocols.

Leela has done for its hotels in Goa pur - other than a pi home, it's also offeri vices of its four- to ter charter planes fr bai and Delhi airpor destinations.

Anuraag Bhatn operating officer of Palaces, Hotels and told TOI, "The de high-end resorts is dication that there is need to travel. Hote sorts

Rashtriya Sahara | 23/8/20

नई दिल्ली। रविवार ○ 23 अगस्त ○ 2020 | राष्ट्रीय सहारा | www.rashtriyasahara.com

लैंड पूलिंग योजना पर डीडीए ने पकड़ी रफ्तार

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने लैंड पूलिंग पर रफ्तार तेज कर दी है। प्राधिकरण के कहना है कि इस योजना को पूर्ण रूप से विकसित होने में 20 साल लगेंगे। डीडीए अभी तक कुल 1371 आवेदनों को सत्यपित कर चुका है।

डीडीए का कहना है कि इस क्षेत्र को मॉर्डन सिटी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। डीडीए की लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत आने वाले दिनों में करीब 200 वर्ग किलोमीटर का इलाका पूरी तरह से विकसित होगा। पॉलिसी में 20 लाख आवास बनकर तैयार होंगे। इससे लगभग 80 लाख से लेकर एक करोड़ लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद डीडीए जता रहा है।

उल्लेखनीय है कि डीडीए ने पॉलिसी में तेज गति से काम करने के लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी मामला मंत्रालय के निर्देश पर वेब पोर्टल भी बनाया था। सिंगल विंडो सिस्टम के तहत इस प्रक्रिया में काम को पारदर्शिता के साथ रखने का प्रयास किया जा रहा है। अब तक विभिन्न एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी योजनाओं के फ्लैट के साथ-साथ आर्थिक कमजोर वर्ग, रोहिणी, द्वारका और नरेला सब-सिटी के लिए भूखंड की बिक्री भी पहले करता रहा है।

20 साल में विकसित होगी पूरी योजना

डीडीए अधिकारी ने बताया कि अगले 20 वर्ष में 20 लाख आवास तैयार होंगे। इसमें लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा और करीब एक करोड़ लोगों को आशियाना भी अलग-अलग दरों पर मिल सकेगा।

डीडीए अधिकारी के अनुसार पिछले वर्ष आरंभ की गई प्रक्रिया में जोन एन, पी-2 व एल में लोगों का सबसे अधिक रुझान दिखा है। सभी पांचों जोन को 109 सेक्टरों में विभाजित किया जा रहा है। अधिकारी ने बताया कि प्राप्त हुए आवेदनों में से 1371 आवेदनों की सेटेलाइट मैपिंग करके भूमि का सत्यापन किया जा चुका है। जल्द ही इलाके के विकास कार्य को शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पॉलिसी में होने वाले सभी निर्माण को रेरा के तहत पंजीकृत किया जाएगा और रेरा का नियम निर्माण पर लागू होगा, ताकि लोगों को सुविधाजनक तरीके से मकानों का आवंटन हो सके।

- जोन-जे, के-1, एल, एन और पी-2 में विभाजित होंगे 109 सेक्टर
- हरेक सेक्टर में होगा 250 से 300 हेक्टेयर भूमि
- 80 हजार से एक लाख लोगों को मिलेगा हर सेक्टर में आशियाना
- ईडब्ल्यूएस श्रेणी में मकान बनाने पर 200 से अतिरिक्त 15 फीसद एफएआर मिलेगा।

कुएं में मिला एक शख्स का शव

नई दिल्ली (एसएनबी)। द्वारका जिले के बाबा हरिदास नगर थाना इलाके के दिचाऊं कला में कुएं से एक शख्स का शव मिला। मृतक का नाम ओम प्रकाश है और वह 11 अगस्त से लापता था। हालांकि परिजनों ने हत्या की आशंका नौकर पर जताई है। जिसके बाद पुलिस हत्या की धाराओं मे केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश कर रही है।

ओमप्रकाश के परिजनों ने उसके लापता होने की सूचना पुलिस को दी थी। परिजनों का आरोप है की पुलिस ने खोजबीन तो की, लेकिन उसका रवैया ढीला-ढाला था, जिसके चलते समय रहते कुछ भी पता नहीं चला। बाद में मृतक ओमप्रकाश के साथ रहने वाला नौकर भी अचानक लापता हो गया और उसने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर लिया।

ओम प्रकाश अविवाहित थे और खेती के साथ-साथ डेयरी का भी काम देखते थे। शुक्रवार को घर से एक किलोमीटर दूर कुएं से उनका शव बरामद हुआ था। बाबा हरिदास नगर थाना पुलिस इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर घरवालों से मिली जानकारी के आधार पर लापता नौकर की तलाश कर रही है।

झपटमारी में महिला धरी गई

नई दिल्ली (एसएनबी)। झपटमारी के आरोप में एक महिला को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक बेटी का रिश्ता टूट जाने के बाद उसने होने वाले दामाद का फोन छीन लिया था। महिला का कहना है कि उसने मोबाइल फोन में सेफ

ऑनलाइन फ्लैट योजना के रेस्पांस से डीडीए की बांछें खिलीं

नई दिल्ली (एसएनबी)। गरीबों के लिए घोषित ऑनलाइन फ्लैट योजना के रेस्पांस से डीडीए की बांछें खिल गई हैं। अधिकारियों ने दावा किया है कि 15 दिनों में कुल 627 इडब्ल्यूएस फ्लैट बुक हो चुके हैं। प्राधिकरण ने यह आवासीय योजना 7 अगस्त को शुरू की थी। खास बात यह है कि सफल आवंटी 28 अगस्त से आवंटन एवं मांगपत्र पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

डीडीए का 15 दिन में 627 फ्लैटों की बिक्री का दावा

डीडीए की इस ऑनलाइन योजना में कुल 916 इब्ल्यूएस फ्लैट शामिल है और सभी नरेला में है। पहले आओ-पहले पाओ श्रेणी की यह योजना पूरी तरह ऑन लाइन है। डीडीए का दावा की फ्लैट की कीमतों में 40 की कटौती की गई है। अब इनकी कीमत 10.89 से 12.29 लाख के बीच है।

डीडीए की इस योजना के लिए वही लोग आवेदन कर सकते है, जिनकी सालाना आमदनी 3 लाख तक है। ऑन लाइन पंजीकरण की राशि 10 हजार रुपए रखी गयी है। डीडीए के मुताबिक सफल आवंटी को फ्लैट की कीमत के भुगतान के लिए 3 महीने का समय मिलेगा।

महिला की हत्या में लिव इन पार्टनर गिरफ्तार

नई दिल्ली (एसएनबी)। मधु विहार इलाके में हुई महिला की हत्या के मामले में उसके लिव इन पार्टनर ब्रह्म सिंह उर्फ काल को गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि

खंगाला, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस टीम ने इसके बाद हुंडई सर्विस सेंटर से संपर्क किया। इस आनंद सिंह से जब संपर्क किया तो पता चला कि आनंद सिंह के जरिये विजेंद्र ने यह कार बल्लभगढ़ सेक्टर [illegible]

डीडीए के 627 रियायती फ्लैट बुक

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) अपनी आवासीय योजनाओं में वापस लौटाए गए या नहीं बिके फ्लैट निर्माण लागत पर 40 फीसद छूट के साथ रियायती दर पर दे रहा है।

डीडीए अधिकारियों के अनुसार डीडीए ने नरेला के पाकेट-1ए सेक्टर ए1-ए4 नरेला के ईडब्ल्यूएस फ्लैट बेचने की ऑनलाइन योजना 7 अगस्त को शुरू की है। इस योजना में फ्लैट पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर आवंटित किए जा रहे हैं। छूट के बाद फ्लैट की अनुमानित लागत करीब 10.89 लाख से 12.29 लाख रुपये के करीब है। अब तक योजना में 916 में से 627 फ्लैट का बुक हो गए हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आय तीन लाख रुपये प्रतिवर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं, परिवार की आय 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

क्रेता मांग व आवंटन पत्र के अनुसार समय से भुगतान करने के लिए अपनी लॉगइन आइडी और पासवर्ड का उपयोग करते हुए डीडीए की वेबसाइट से 28 अगस्त से मांग व आवंटन पत्र (डीएएल) ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। मांगी गई राशि 3 महीने की अवधि के अंदर जमा करवानी होगी, नहीं तो फ्लैट रद कर दिया जाएगा।

लैंड पूलिंग पॉलिसी के लिए मिले आवेदन: डीडीए को लैंड पूलिंग पॉलिसी के लिए 1371 आवेदन मिल चुके हैं। जल्द ही डीडीए की ओर से लैंड पूलिंग जोन-एन के सेक्टर पी-2 और एल के विकास की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। गौरतलब है लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत किसी जोन का विकास कार्य तभी शुरू हो सकता है जब तक उस जोन में 70 फीसद भूमि विकास के लिए डीडीए के पास उपलब्ध हो जाए।

अनुबंधित नर्सिंग कर्मियों को सता रहा नौकरी जाने का डर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में स्थायी नर्सों की नियुक्ति की है। इसके मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को नियुक्त नर्सिंग कर्मचारियों को जल्द ज्वाइन कराने व सात दिन में उसकी रिपोर्ट विभाग को भेजने का निर्देश दिया है। साथ ही अनुबंध पर कार्यरत नर्सिंग कर्मचारियों की सेवाएं दिसंबर तक [illegible] नीति बनाकर अनुबंधित कर्मचारियों को स्थायी करने का आदेश दिया था, फिर भी स्थायी नहीं किया गया। अभी कर्मचारियों का अनुबंध फरवरी 2021 तक है। लेकिन, स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर दिसंबर 2020 तक ही सेवाएं जारी रखने की बात कही है। इस वजह से दो हजार नर्सिंग कर्मचारी बेरोजगार हो सकते हैं। [illegible]

	2 व 3 के [illegible] एवं पुनर्निर्माण कार्य।
5	एल.डी.आर.एफ. [illegible] 202 मोटर मार्ग के [illegible] का पुनर्निर्माण कार्य।
6	एल.डी.आर.एफ. वर्ष 202 [illegible] से 10 में अतिरिक्त [illegible]
7	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 202 किमी. 41 में अतिरिक्त [illegible]
8	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2020 दीवार का निर्माण कार्य।
9	विशेष मद के अंतर्गत [illegible] कार्य।
10	राज्य योजना के अंतर्गत [illegible] पैरापिट का निर्माण एवं [illegible]
11	जिला योजना वर्ष 2019-20 [illegible] सुरक्षा दीवार कार्य।
12	राज्य योजना के अंतर्गत [illegible] मोटर मार्ग के किमी. [illegible] का निर्माण कार्य।
13	पूल्ड आवास योजना के अंतर्गत [illegible] बदलने एवं अन्य [illegible] कार्य।
14	जिला योजना वर्ष 201[illegible]-16 के [illegible]
15	वार्षिक अनुरक्षण के अंतर्गत [illegible] कण्डोला झूला पुल, [illegible] टेम-शेगन का कार्य।

निविदा दिनांक 11-09-2020 [illegible]
नोट-क्रम संख्या 1 से 8 एवं 13, [illegible]
पत्रांक 12777/मु.[illegible]/22[illegible]

पूर्वी दिल्ली [illegible]

अपर निदेशक अस्पताल प्रशासन (चिकित्सा एवं [illegible])
सं.:-एडीईएल.डीएचए(एम एण्ड टीबी)/ईडीएमसी/2020/465
वर्ष 2021-23 के लिए द्विवार्षिक आधार पर पूर्वी दिल्ली नगर निगम के स्वास्थ्य [illegible] सामान्य मदों इत्यादि की खरीद के लिए दर, संविदा एवं एजेंसी को नियत करने [illegible] निविदा की अनुमानित देयता 40 करोड़ रु. प्रतिवर्ष है। निविदा की महत्वपूर्ण अनु[illegible]

क्र. सं.	निविदा सं.	निविदा का विवरण	निविदा दस्तावेज खरीदना एवं डाउनलोड करना	ऑनलाइन बोली तैयार करना एवं बैंक प्रस्तुत करना
1.	16439 16444 16449 16450 16452	Gr. I Gr. VI Gr. XI Gr. XII Gr. XV	24.08.2020 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से 21.09.2020 को अपराह्न 15:00 बजे तक	24.08.2020 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से 22.09.2020 को अपराह्न 15:00 बजे तक
2.	16451	Gr. XIII	24.08.2020 को [illegible]	[illegible]

किया। पुलिस आने से पहले मेंटिनेंस टीम ने लिफ्ट ऑपरेटर को भेजकर फंसे हुए युवक को बाहर निकलवा दिया।

पुलिस के आने पर उन्हें समस्याएं बताई। यह भी बताया कि हर ब्लॉक में कोई न कोई लिफ्ट खराब है। पुलिस से बात करने के दौरान ही दूसरे ब्लॉक में लिफ्ट में 3 लोग फंस गए। उन्हें भी बाहर निकाला गया। यहां रहने वाले लोग शिकायत कर रहे थे, तब एओए या मेंटिनेंस टीम की ओर से कोई मौजूद नहीं था।

निकालने का दावा कर रहे हैं।

यह सर्जरी 18 अगस्त को हुई और महिला अब पूरी तरह से ठीक है। उन्हें शनिवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अस्पताल के अनुसार, इससे पहले साल 2017 में कोयम्बटूर में एक महिला के पेट से 34 किलोग्राम का ओवेरियन ट्यूमर निकाला गया था। इस महिला का इलाज करने वाले गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और बैरिएट्रिक सर्जन डॉ. अरुण प्रसाद ने कहा ... साथ पीड़ित महिला का वजन भी ...

पेट का साइज काफी फूलता ... में पीड़ित महिला को लगा कि ... है। लेकिन एक दिन उनका ... किलोग्राम हो गया। इससे पिछले

NBT-23/8/20

3 जोन में 70 प्रतिशत जमीन हुई पूल

डीडीए की लैंड पूलिंग योजना को 18 महीने में मिली कुछ कामयाबी

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

डीडीए की लैंड पूलिंग योजना को 18 महीने में तीन जोन के सात सेक्टरों में 70 प्रतिशत जमीन पूल होने संबंधी आवेदन पोर्टल पर मिल चुके हैं। इस योजना के लिए अभी कंसोर्टियम बनाना होगा। राजस्व विभाग के जमीन के दस्तावेजों की वेरिफिकेशन प्रक्रिया के बाद डीडीए जमीन मालिकों को नोटिस जारी करेगा।

एक सेक्टर के सभी आवेदकों को एक औपचारिक अनुबंध करना होगा। उसमें अपने शेयर के साथ ही प्रावधानों, जैसे- आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए फ्लैट बनाने की शर्त का पालन करना होगा। डीडीए के अधिकारियों का कहना है कि अब तक कुल जमीन में से करीब 33 प्रतिशत जमीन पूल हो गई है। धीरे- धीरे पॉलिसी के प्रभाव दिखने लगेंगे। जोन एल, एन और पी-2 में काफी अच्छी प्रोग्रेस है। डीडीए ने योजना में

आवेदन करने के लिए सभी गांव के लिए 5 फरवरी से 6 अक्टूबर 2019 के बीच विंडो खोली थी। उसमें 6071 आवेदन के साथ 6409 हेक्टेयर जमीन पंजीकृत हुई थी। दूसरी बार 13 गांव के लिए 3 जनवरी से 15 फरवरी 2020 तक दूसरी बार विंडो खोली गई। इसमें 71 आवेदन के साथ 78 हेक्टेयर जमीन पंजीकृत हुई। तीसरी बार सभी गांव के लिए 11 मार्च से 24 मार्च के बीच विंडो खोली गई। इसमें 77 आवेदन के साथ 94 हेक्टेयर जमीन पंजीकृत हुई।

अब तक 6212 आवेदन के साथ 6575 हेक्टेयर जमीन पंजीकृत हुई है। इनमें से राजस्व विभाग ने अब तक 1371 आवेदन की जमीन के दस्तावेजों की जांच पूरी कर ली है। लैंड पूलिंग योजना में पांच जोन जे, के-1, एल, एन और पी-2 में आने वाले 95 गांव को शामिल किया गया है। इस जमीन को 109 सेक्टर में बांटा गया है। एक सेक्टर में करीब 250 से 350 हेक्टेयर जमीन है। इसमें 80 हजार से 1 लाख तक लोग रह सकते हैं। कुल योजना में 20 हजार हेक्टेयर के करीब जमीन पूल होनी है।

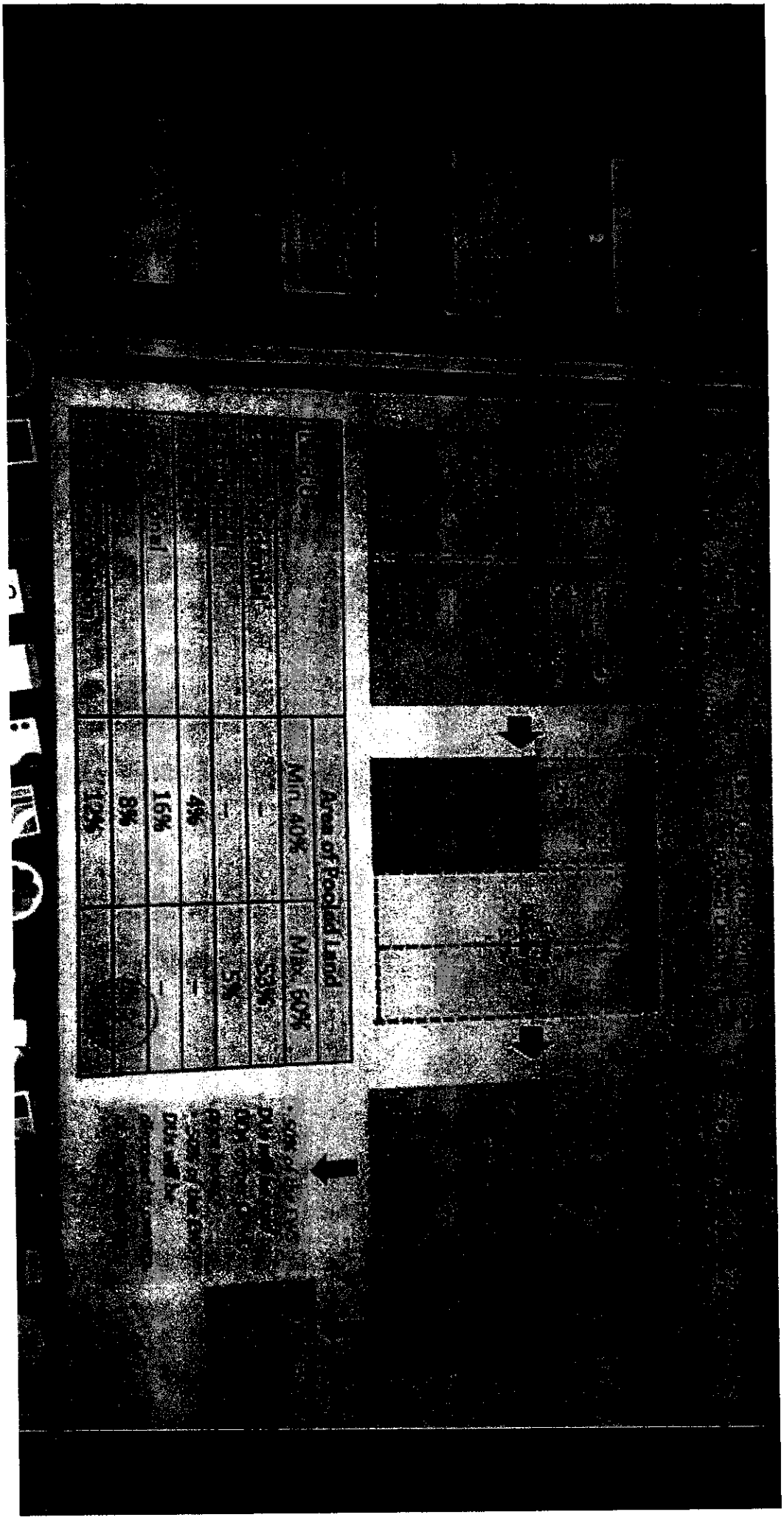

Area of Pooled Land
Min. 40%
Max. 60%
53%
5%
4%
16%
8%
12%

नई दिल्ली
सोमवार • 29 जून, 2020

लैंड पूलिंग के विभिन्न जोन में विकास का खाका खींचेगा डीडीए

पहल

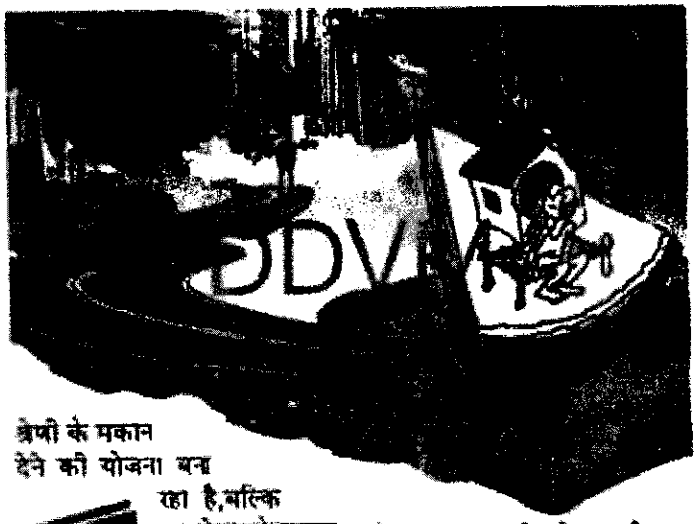

- अब तक 4 जोन में ही मुख्य तौर पर मिली है सर्वाधिक जमीन
- सेक्टरों के नामकरण के लिए मांगे जा चुके हैं लोगों से सुझाव

नई दिल्ली, 28 जून (नवोदय टाइम्स): लैंड पूलिंग पॉलिसी में भले ही अभी तक किसी भी आवेदक को निर्माण या अन्य कार्य के लिए स्वीकृति नहीं दी गई है। लेकिन डीडीए ने अब इस पालिसी में स्टॉक होल्डरों सहित आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए विकास का खाका किस तरह से तय हो, इसके लिए जनता की सलाह ली जाएगी।

> बड़े किसान, डेवलपरों से आवेदन के साथ मांगा जा रहा प्लान

बताया जाता है कि पॉलिसी में भूमि संग्रहित करके देने वाले बड़े किसान, डेवलपरों से विकास का प्लान भी आवेदन के साथ मांगा जा रहा है। यह प्लान केवल संबंधित जमीन से ही नहीं, बल्कि जोन में किस तरह से इलाके को विकसित किया जाए, इस पर भी होगा।

दरअसल लैंड पूलिंग पॉलिसी के जरिए डीडीए [illegible] उनकी पसंद के आधार पर ही हर श्रेणी के मकान देने की योजना बना रहा है, बल्कि इस योजना के माध्यम से उसने किसानों से जमीन अधिग्रहण के दौरान पेश आने वाली दिक्कत से भी दूर होने का रास्ता खोजा है। यही वजह है कि पिछले दिनों डीडीए ने लोगों की भागीदारी लैंड पूलिंग पॉलिसी में बढ़ाने के इरादे से जोन के विभिन्न सेक्टरों के नामकरण को लेकर भी राय पूछी थी।

डीडीए के अनुसार पॉलिसी में कोरोना की वजह से लॉकडाउन से पहले ही विभिन्न जोन में पॉलिसी के तहत 6113 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 6449 हेक्टेयर जमीन का पंजीकरण अब तक हुआ है। अधिकारी ने बताया कि जोन एन में भूमि अधिक संख्या में मिली है और यहां बसावट व अन्य सुविधाओं के जल्द विकसित होने की संभावनाओं को देखते हुए इस जोन के सेक्टर-20 व सेक्टर 21 में विकास कार्य पर सबसे पहले ध्यान देने का काम आरंभ किया है। उन्होंने बताया कि अन्य इलाके में भी ग्रामीणों को पॉलिसी का फायदा समझाने के लिए जल्द ही शिविर आयोजित किया जा सकता है। पॉलिसी में लोगों की भागेदारी अधिक बढ़ाने के लिए इलाकेवार विकास किस प्रकार से हो, इस पर राय भी ली जा रही है।

लैंड पूलिंग में पंजीकरण के लिए तय राशि

अधिकतम पंजीकरण शुल्क	50,000 रु.
1-10 हेक्टेयर तक	2000 रु. प्रति हेक्टेयर
11-20 हेक्टेयर भूमि पर	1000 रु. प्रति हेक्टेयर
21 हेक्टेयर से अधिक...	500 रु. प्रति हेक्टेयर

किस-किस सेक्टर में होगा विकास

- जोन के-1—क्रमशः 281, हेक्टेयर
- एल—1659 हेक्टेयर
- एन—3294 हेक्टेयर
- पी-2—1261 हेक्टेयर
- जे में सिर्फ 4 हेक्टेयर भूमि का रजिस्ट्रेशन किया गया
- कुल 109 सेक्टरों को पांच जोन में किया जाएगा विकसित
- लैंड पूलिंग के तहत पांच जोन में होगा मुख्य विकास
- करीब 17 लाख आवास होंगे तैयार
- लगभग पांच लाख किफायती आवास हो सकते हैं तैयार
- तीन नई सब सिटी को विकसित करने में मिलेगी सहायता